जनसत्ता

आतंक के खिलाफ

जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अगला कदम बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन बुलाने को कहा है। भारत की यह मांग प्रासंगिक है और सम्मेलन की जरूरत को रेखांकित करती है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी रूप में आतंकवाद के शिकार हैं और इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, अरबों-खरबों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। आतंकवाद अब कितना भयावह रूप ले चुका है, यह किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम एशिया तो लगता है आतंकवाद का केंद्र ही बन गया है। लेकिन दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है जिससे इस समस्या से निपटने के लिए ठोस और सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और पीड़ित देश मिल कर मुकाबले की रणनीति बना सकें। इसकी बड़ी वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में ही खेमेबाजी है और खासतौर से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी ऐसी समस्या से निपटने के लिए एकजुट नहीं हो पाते। वे अपने हितों में उलझे पड़े हैं।

दो महीने पहले न्यूजीलैंड और पिछले महीने श्रीलंका में हुए हमले बता रहे हैं कि आतंकवाद ने किसी देश को नहीं छोड़ा है। न्यूजीलैंड की मस्जिदों पर हमले स्तब्ध कर देने वाले थे। श्रीलंका में बौद्ध व मुसलिम समुदाय में टकराव होते रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष वैसी गंभीर चुनौती नहीं बने थे जैसे पिछले महीने ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों को निशाना बनाया गया। यह साफ हो चुका है कि श्रीलंका में इस आतंकी हमले के पीछे इसलामिक स्टेट (आइएस) का हाथ था और इसे न्यूजीलैंड के हमले का बदला बताया जा रहा था। हाल में अमेरिका के कुछ शहरों में यहूदी धर्म स्थलों पर हमले हुए, पहले भी होते रहे हैं। अमेरिका अलकायदा का सबसे बड़ा आतंकी हमला झेल चुका है। यूरोप का शायद ही कोई देश बचा हो जहां आतंकी हमले न हुए हों। ऐसे में क्यों नहीं आतंकवाद पीड़ित देशों को मिल-बैठ कर रणनीति बनाने पर विचार करना चाहिए!

भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन बुलाने के लिए एक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र में 1986 में पेश किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सदस्य राष्ट्रों के बीच आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक राय नहीं बन पाई और यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। आठवें दशक में भारत ने पंजाब में आतंकवाद की पीड़ा झेली थी। पंजाब में आतंकवाद अलग खालिस्तान की मांग को लेकर शुरू हुआ था, और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ जो आज तक कायम है। लेकिन तब दुनिया के देश भारत के साथ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वे खुद आतंकवाद से त्रस्त नहीं थे। हकीकत यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया के असहाय देश जिन बड़े अधिकार-संपन्न देशों की ओर देखते हैं और उनसे उम्मीदें लगाते हैं वही दुनिया में आतंकवाद पनपाने के लिए जिम्मेदार भी हैं। पाकिस्तान दुनिया में आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना है, यह जानते हुए भी अमेरिका और चीन उसके हमदर्द हैं। दरअसल वैश्विक राजनीति में आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कुछ देशों की रणनीति का हिस्सा ही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कर भी क्या सकता है!

धरोहर और उदासीनता

धरोहरें संभालने के मामले में हमारे देश में प्रायः उदासीनता ही दिखाई देती है। निजी संपत्तियों से लेकर सार्वजनिक इमारतों तक के मामले में यही आलम है। हिंदी फिल्म जगत में इतिहास रचने वाला आरके स्टूडियो का बिक जाना इसकी ताजा मिसाल है। आरके स्टूडियो की स्थापना अभिनेता, फिल्म निर्माता राज कपूर ने पाई-पाई जोड़ कर की थी। इस स्टूडियो में अनेक नामचीन फिल्मों का फिल्मांकन हुआ। सिने दर्शकों में इस स्टूडियो को लेकर एक भावनात्मक लगाव था। मगर व्यावसायिक दबाव और बदलते जमाने की कारोबारी होड़ में यह स्टूडियो अपने हाल पर बिसूरता रहा। राज कपूर के न रहने के बाद उनके बेटे और दूसरे परिजन इसकी देखभाल नहीं कर पाए। काफी समय तक कपूर खानदान की बहू जेनिफर नाटकों का आयोजन कर इस स्टूडियो की विरासत को बचाए रखने का प्रयास करती रहीं, पर वे भी विफल रहीं। एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान स्टूडियो में आग लगी और आखिरकार कपूर परिवार ने इसे बेचने का फैसला किया। अब उस पर गोदरेज समूह का स्वामित्व हो गया है। गोदरेज कंपनी वहां आलीशान रिहाइश और कारोबार केंद्र बनाएगी।

इस जमाने में जब मुंबई फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र है, फिल्मों का कारोबार काफी बढ़ चुका है। इसमें तकनीक का भरपूर उपयोग होने लगा है। बहुत सारे फिल्मकार जगह न मिलने के कारण मुंबई से बाहर फिल्मांकन के लिए जगह तलाश करते हैं। अगर आरके स्टूडियो को बदलते समय के अनुसार कारोबार की तरह विकसित किया जाता, तो आज उसकी यह दशा न होती, जो हुई है। मगर राज कपूर के वारिस अभिनय और दूसरे जरिए से अपने जीवन-यापन करते रहे, स्टूडियो की विरासत को बचाए रखने को लेकर उदासीन ही देखे गए। कुछ पेचीदगियां इसके स्वामित्व को लेकर भी थीं, पर उन्हें सुलझाना कठिन नहीं माना जा सकता। दूसरे, इसे संभालने में आर्थिक तंगी भी बड़ा कारण नहीं हो सकता था। आजकल फिल्म स्टूडियो बनाने, संभालने के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो जाता। बस, जरूरत थी तो इसे कारोबारी शक्ल देने की, जो कपूर खानदान नहीं दे पाया। काश, इसे कोई ऐसी कंपनी लेती, जो उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रख पाती। वहां रिहाइशी और कारोबारी केंद्र बनने से स्टूडियो की पहचान तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरे अनेक देशों में ऐसी विरासतों को संभालने में सरकार भी दखल देती है, मगर हमारे यहां ऐसी कोई रीति-नीति नहीं है। इसी का नतीजा है कि निजी प्रयासों से बने ऐसे कई ठिकाने बिला गए।

ऐतिहासिक महत्त्व की निजी संपत्तियों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के सरकारी प्रयास की तो क्या उम्मीद की जाए, सरकारें खुद अपने यहां मौजूद ऐतिहासिक महत्त्व के भवनों, जगहों, स्मारकों आदि को संरक्षित नहीं कर पातीं। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, पर उसे ध्यान में रख कर न तो ऐतिहासिक महत्त्व की चीजों को सहेजने का कोई उत्साहजनक प्रयास दिखता है, न उनके बारे में विश्व स्तर पर प्रचार-प्रसार का कोई जतन। अब ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतों की साज-संभाल की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने का एक नया चलन शुरू हुआ है। लाल किला इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में निजी प्रयास से बनी मशहूर जगहों-भवनों को बचाने में भला सरकारी दखल की क्या बात की जा सकती है। ऐसी जगहें सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं होतीं, वे अपने जमाने का इतिहास भी होती हैं। इसलिए इस मामले में व्यावहारिक नीति पर विचार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

कल्पमेधा

उचित अवसर के अभाव में योग्यता का मूल्य बहुत कम रह जाता है।
-नेपोलियन

विदेश व्यापार घाटे की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

अब यह जरूरी है कि सरकार निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दे, जैसे- अन्य देशों की गैर शुल्कीय बाधाएं, मुद्रा का उतार-चढ़ाव और सेवा कर। तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी आयात पर कुछ नियंत्रण करना होगा। जबकि निर्यात की नई संभावनाएं खोजनी होंगी।

पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में देश के आयात बिल जिस तरह बढ़ा है उससे विदेश व्यापार घाटे का ग्राफ चढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक वर्ष 2018-19 में भारत का निर्यात नौ फीसद बढ़ कर तीन सौ इकतीस अरब डालर पर पहुंच गया। यद्यपि निर्यात का यह रिकॉर्ड स्तर है, लेकिन निर्यात के साढ़े तीन सौ अरब डालर के लक्ष्य से कम ही है। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष में देश का आयात भी करीब नौ फीसद बढ़ कर पांच सौ सात अरब डालर मूल्य का रहा। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापार घाटा बढ़ कर करीब एक सौ छिहत्तर अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर रहा, जो वर्ष 2017-18 में 162 अरब डालर था।

हालांकि चीन से पिछले वित्त वर्ष में व्यापार घाटे में कमी आई है, लेकिन इससे देश के बढ़ते हुए विदेश व्यापार घाटे के कम होने के मद्देनजर अधिक असर नहीं दिखा है। हाल में प्रकाशित भारत-चीन व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब अट्ठासी अरब डालर रहा। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि पहली बार भारत, चीन के साथ व्यापार घाटा दस अरब डालर तक कम करने में सफल रहा है। भारत का व्यापार घाटा करीब बावन अरब डालर रहा। पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। चीन के बाजार तक भारत की अधिक पहुंच और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे मौजूदा व्यापार युद्ध के कारण पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़ कर अठारह अरब डालर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में तेरह अरब डालर था। इतना ही नहीं, चीन से भारत का आयात भी छिहत्तर अरब डालर से कम होकर सत्तर अरब डालर रह गया।

वर्तमान में चीन भारतीय उत्पादों का तीसरा बड़ा निर्यात बाजार है। चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। दोनों देशों के बीच 2001-02 में आपसी व्यापार महज तीन अरब डालर था जो 2018-19 में बढ़ कर करीब अट्ठासी अरब डालर पर पहुंच गया। चीन से भारत मुख्यतः इलेक्ट्रिक उपकरण, मशीनी सामान, कार्बनिक रसायन उत्पाद आदि आयात करता है। वहीं भारत से चीन को मुख्य रूप से खनिज, ईंधन और कपास आदि का निर्यात किया जाता है। पिछले एक दशक के दौरान चीन ने भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पैठ बढ़ाई है। लेकिन 2018-19 में पहली बार चीन से होने वाले आयात में कमी आई। यह भारत-चीन व्यापार को रेखांकित करने वाला नया तथ्य है। भारत ने पिछले महीने ही चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में व्यापार घाटे को कम करने के लिए तीन सौ अस्सी उत्पादों की सूची चीन को भेजी है, जिनका चीन को निर्यात बढ़ाया जा सकता है। इनमें मुख्य रूप से बागवानी, कपड़ा, रसायन और औषधि क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय देश के व्यापार घाटे के सामने एक बड़ी चुनौती अमेरिका की ओर से आती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर अन्यायपूर्ण तरीके से आयात शुल्क लगाए गए हैं। अब अमेरिका भी भारत को विभिन्न प्रकार की निर्यात संबंधी रियायतों पर नियंत्रण करेगा। अमेरिका जल्द ही भारत को दी गई प्राथमिकताओं की सामान्यीकरण प्रणाली (जीएसपी) का दर्जा समाप्त कर सकता है। अमेरिका से मिली व्यापार छूट के तहत भारत से किए जाने वाले करीब 5.6 अरब डालर यानी चालीस हजार करोड़ रुपए के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अमेरिका द्वारा भारत से आयात को दी जा रही तरजीही बंद करने से भारत में कपड़े, रेडीमेड कपड़े, रेशमी कपड़े, प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ, फुटवियर, प्लास्टिक के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, हाथ के औजार, साइकिल के पुर्जों जैसी संबंधित औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन उद्योगों की मुश्किलें बढ़ने से इनमें कार्यरत हजारों लोगों के सामने नौकरियां जाने का खतरा भी खड़ा है।

चूंकि इस समय देश से निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की डगर पर कुछ और चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, कनाडा,

रूस, श्रीलंका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने अमेरिका के साथ मिल कर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की निर्यात संवर्धन योजनाओं के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अब भारत अपने निर्यातकों के लिए सब्सिडी योजनाएं लागू नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना डब्ल्यूटीओं के समझौते का उल्लंघन है।

निश्चित रूप से निर्यात परिदृश्य पर दिखाई दे रही मुश्किलों को दूर करना होगा। भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन) का कहना है कि भारत के मुकाबले कई छोटे-छोटे देश मसलन- बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों ने अपने निर्यातकों को भारी सुविधाएं देकर भारतीय निर्यातकों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। निर्यातकों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में रिफंड संबंधी जो कठिनाई आ रही है, उसे दूर किया जाना होगा। निर्यात को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और सभी निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी बहाल की जानी चाहिए। सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि के दीर्घकालिक प्रयासों के तहत निर्यात कारोबार का कमजोर बुनियादी ढांचा सुधारे जाने की जरूरत है। खासतौर से समुद्री व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रीय कारोबारी समूहों और मुक्त व्यापार समझौतों के क्षेत्र में पूरा नियंत्रण हासिल करना होगा। सार्क देशों- श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को भारतीय निर्यात बढ़ने की संभावनाएं हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका में भी निर्यात बढ़ने की संभावना है। इसी तरह म्यांमा और मलेशिया सहित आसियान देशों को भी निर्यात बढ़ सकते हैं।

अब यह जरूरी है कि सरकार निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दे, जैसे- अन्य देशों की गैर शुल्कीय बाधाएं, मुद्रा का उतार-चढ़ाव और सेवा कर। तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी आयात पर कुछ नियंत्रण करना होगा। जबकि निर्यात की नई संभावनाएं खोजनी होंगी। इस समय भारत-चीन के बीच व्यापार बढ़ने और भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने का जो नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसका भरपूर लाभ लिया जाना चाहिए। चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए हमें चीन के बाजार में भारतीय सामान की पैठ बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों को समझना होगा, जहां चीन को गुणवत्तापूर्ण भारतीय सामान की दरकार है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मामले में भारत चीन से बहुत आगे है। देश से कृषि निर्यात की नई

संवादहीनता के खतरे

आलोक रंजन

दुनिया मेरे आगे

हमारे विद्यालय में सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने वाले उपकरण लगाए जा रहे थे। इस कारण पूरे परिसर में जगह जगह से काटने, ठोकने-पीटने की आवाजें आ रही थी। वे वही दिन थे जब बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। वह समय विद्यार्थियों के गहन अध्ययन का होता है। ऐसे में इस तरह की आवाजें उनका ध्यान भटका रही थीं। उनमें से एक छात्रा मेरे पास आई। उसे उन आवाजों से परेशानी हो रही थी। एक को शिकायत करते देख बाकी विद्यार्थियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं इसे उनसे ही हल करवाना चाह रहा था। मैंने खिड़की की पास बैठी एक छात्रा से कहा कि वहां खड़े नजदीकी व्यक्ति को बोलो कि तुमलोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वे इस काम को अभी बंद कर दें और बाद में करें जब विद्यार्थी न हों। उस छात्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। मैंने दूसरी छात्रा से कहा, तो उसका भी वही हाल। पूछने पर पता चला कि वे समझ नहीं पा रही हैं कि काम करने वाले लोगों को क्या कह कर संबोधित करें! मेरे लिए यह नई बात थी। यह संबोधन के शब्द के न होने का मामला भर नहीं था, बल्कि बात अनजान पुरुषों को कैसे संबोधित किया जाए, उसकी थी।

पिछले दिनों दिल्ली के एक कैफे में भी यही बात देखने को मिली। वहां ज्यादातर कर्मचारी लड़कियां थी। उन सबके दोपहर के भोजन का समय था, सो दो लड़कियां हमारे पीछे की खाली टेबल पर आकर बैठ गईं और खाने लगी। थोड़ी देर बाद काउंटर पर काम कर रही एक लड़की ने उनकी ओर किसी बात के लिए इशारा किया। वे दोनों खाने में मशगूल थीं। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पीछे मुड़ कर उन्हें बता दिया कि काउंटर से आप लोगों के लिए कोई संदेश है। मैं उन्हें बोल कर मुड़ा ही था कि मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उनकी बातों का मतलब यह था कि लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी छात्राएं याद आ गईं। उनके लिए सवाल अनजान पुरुषों से बात करने का था और यहां अनजान लड़कियों से। वे तय नहीं कर पा रही थीं कि वे कैसे बात करें और यहां मैंने कर ली तो यह ठीक नहीं माना गया।

असल में यह समस्या बहुत गहरी है। अपने देश में विपरीत लिंग के व्यक्ति से बात करने का नजरिया सहज नहीं है। परिवार से लेकर विद्यालयों तक में इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। लड़कियों के मामले में बात बहुत ही अलग तरह से काम करती है। उन्हें अनजान लड़कों या पुरुषों से बात न करना सिखाया जाता है। इसकी अपनी वाजिब वजहें हैं। इससे उनके मन में अनजान पुरुषों के प्रति भय-मिश्रित संकोच सामान्य रूप से पाया जाता है। आगे यही और अलग-अलग तरीकों से काम करता है। पुरुषों से सीधे-सीधे बात करने वाली स्त्री को समाज स्वस्थ दृष्टि से नहीं स्वीकार करता है। लोग उन्हें कई निकृष्ट विशेषण से संबोधित करने से नहीं चूकते। वहीं पुरुषों से बात न करने वाली और शरमाते-सकुचाते हुए बात करने वाली स्त्री को 'सुशील' स्त्री माना जाता है।

समाज की इस मानसिकता को समझने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास नजरें फिराते ही यह दिख जाता है। लड़कों की बात करें तो हमारा समाज इस मामले में काफी

अजहर पर शिकंजा

भारत के हर शहीद जवान के लिए प्रत्येक भारतीय के सीने में जो आग धधक रही थी, उसे थोड़ी राहत मिली है। हाल ही में पुलवामा में सीआरपीएफ के चालीस जवानों को मार दिया गया था। इस घटना के बाद पूरा देश तिलमिलाया हुआ था कि आतंकी मसूद अजहर को शिंकजे में लाया जाए। आखिरकार भारत अपनी इस कूटनीति में कामयाब हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति के सदस्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार-बार चीन इस पर वीटो लगा दे रहा था। लेकिन अब उसने अंतराष्ट्रीय दबाव पड़ने के बाद इस बार वीटो नहीं किया और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में साथ खड़ा हुआ। अगर इसे एक सियासी नजरिए से देखा जाए तो चुनाव के समय में आतंकवाद पर इतनी बड़ी करवाई कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के पक्ष में है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी चीन और अमेरिका भारत का इसी तरह संथईन करेंगे और पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे ताकि वह वांछित अपराधियों को भारत के हवाले करे।

● *शिवानी पटेल, कानपुर*

वंशवाद से मुक्ति

आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहां राजनीति में आने का मकसद जन समस्याओं का समाधान या देशहित नहीं, बल्कि अकूत धन संचय और अपने को समाज के एक आम नागरिक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बहुत ज्यादा शक्ति-संपन्न बनाना भी है। भारत में नेताओं को बहुत ही ठाठबाट, ठसक और जेड सुरक्षा के साथ ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की आदत पड़ गई है। इसलिए यहां कुछ अपवादों को छोड़ दें तो लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने परिवार को राजनीति जैसे 'व्यवसाय' में लाना चाहते हैं। भारतीय राजनीति का एक दुखद पहलू यह भी है कि 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में जो राजा-रजवाड़े इस देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वे सभी आज सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल आदि पदों पर बैठ कर इस देश के कथित नियंता बने हुए हैं। चूंकि यहां की जनता अधिकांशतः अशिक्षित है और जाति, धर्म जैसे खांचों में बंटी हुई है, इसलिए फिलहाल भारतीय राजनीति से 'परिवारवाद' की बुराई समाप्त होने की उम्मीद कम ही है। फिर भी जनता जैसे-जैसे जागरूक होती जाएगी, वही इस वंशवाद और परिवारवाद की बुराई का शमन भी करेगी ।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

सरकार और जिम्मेदारी

दिनोंदिन बढ़ रही जनसंख्या के साथ-साथ नौकरियों की संख्या बढ़ने की भी जरूरत थी। लेकिन सरकार में तो कई प्रकार के पद ही समाप्त कर दिए गए। ऐसा कदम तो कल्याणकारी राज्य के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के संदर्भ में सरकारी नियंत्रण कम से कम होता जा रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति अपने जीवन पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप तो चाहता है, लेकिन जीवन रक्षा के संदर्भ में राज्य से उसकी प्रासंगिकता की मांग करती है। राज्य और सरकार का निर्माण इसलिए हुआ ताकि वह जनता के टैक्स के बदले उसको न केवल स्वतंत्रता और सुरक्षा देगी, बल्कि विकास के तमाम अवसर मुहैया करा कर व्यक्ति के अस्तित्व संवर्धन के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में मददगार होगी। लेकिन हकीकत के धरातल पर जनसंख्या के अनुपात में सरकार शिक्षक भी मुहैया नहीं कराती, जिसका परिणाम आधे-अधूरे विकास के रूप में सामने आता है। इसी तरह जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की बहाली नहीं की जाती। जबकि दिनों दिन बीमार और बीमारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन की स्थापना की गई, लेकिन आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति कैसी कैसी छवि है, यह जगजाहिर है।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली